Furnishing of Returns of immovable property by Officers of Public Sector Undertakings

2870 SHRI SAMAR MUKHERJEE

SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI

Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) whether there are instructions issued by the Department of Personnel that returns of immovable property etc to be furnished every year,

(b) if so, whether public sector undertakings also come within the purview of these rules,

(c) if so, the number of officers in each undertaking not strictly following the rules,

(d) the action taken against the officials for not complying with the order,

(e) whether Government propose to issue order afresh in that matter, and

(f) if not the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI H M PATEL) (a) and (b) Government have in consultation with the Central Vigilance Commission circulated certain Model Conduct, Disciplinary & Appeal Rules for adoption by the Central Government enterprises According to these rules, all officers of the public enterprises are required to report the movable, immovable and other valuable properties in their possession as well as obtain permission for any transactions in them Non-compliance with these rules will make the employees liable to disciplinary action

(c) to (f) The rules referred to in the reply to parts (a) & (b) of the Question are already being complied with by the bulk of the Public Enterprises As regards a few Enterprises which have not yet incorporated the rules in question in their service conditions, fresh instructions are being issued reiterating the Government's policy in this regard so as to ensure full compliance with the Government's policy by all the Public Enterprises

औद्योगिक गृहो द्वारा [illegible] स के लिये अपनाये गये [illegible]

2871 डा० रा जी सिंह क्या वित्त मंत्री यह बताने की [illegible] करेंगे कि

(क) क्या देश [illegible] बड़े औद्योगिक गृहो ने विकास कार्यों [illegible] लिये कुछ गावो को अपनाया है ,

(ख) प्रत्येक औद्योगिक गृह ने बिहार के किन किन गावो को अपनाया है और

(ग) क्या इस तथ्य के बावजूद कि बिहार की आर्थिक दशा [illegible] खराब है उपरोक्त गाव विकास योजना के मामले में इसके साथ भेदभाव किया गया है ?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्लाह) ( ) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रो के विकास के सम्बन्ध में 64 कम्पनियो के कार्यक्रमो को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35गग के अधीन स्वीकृति दे दी गई है । इन कार्यक्रमो में से इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये कुछ कार्यक्रम [illegible] जिन्हे बिहार में गामिया के निकट [illegible] ग्राम में कार्यान्वित किया जाना है ।

दि एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ने ग्रामीण क्षेत्रो के विकास कार्यक्रमो की स्वीकृति [illegible] लिए हाल ही मे एक आवेदन दिया है उक्त कार्यक्रमो में से कुछ कार्यक्रमो को [illegible] के सिंहभूम और राची जिलो के अन्तर्गत आने वाले ग्रामो में कार्यान्वित करने [illegible] है और [illegible] पर निर्धारित प्राधिकार [illegible] विचार किया जायगा